

विनियोग संख्या 63 - भारत का उच्चतम न्यायालय
APPROPRIATION No. 63-SUPREME COURT OF INDIA

			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
प्रभारित-	Charged-				
मूल	Original	33,05,00	39,51,00	33,57,62	-5,93,38
पूरक	Supplementary	6,46,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,68,00
टीका और टिप्पणियां					Notes and comments

1. विनियोग में, कुल बचतें (593.38 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 646.00 लाख रु. के पूरक विनियोग का 92 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 15 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

1. In the appropriation, the overall savings (Rs.593.38 lakhs) constituted 92 percent of the supplementary appropriation of Rs.646.00 lakhs obtained in February, 2004 and 15 percent of the total sanctioned appropriation.

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	3305.00	3383.00	3357.62	-25.38
पू.	S.	646.00			
पु.	R.	-568.00			

(I) "उच्चतम न्यायालय - स्थापना" (प्रभारित) के अंतर्गत 3305.00 लाख रु. के मूल विनियोग को 646.00 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर 3951.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो माननीय न्यायाधीशों के कुछ पदों को न भरे जाने और वकीलों के चेम्बरों का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए स्थगित कर दिए जाने के कारण 593.38 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Supreme Court - Establishment" (Charged) - the original appropriation of Rs.3305.00 lakhs was augmented to Rs.3951.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of Rs.646.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.593.38 lakhs - due to non-filling up of some posts of honourable judges and postponement of construction of lawyer's chambers to 2004-05 by the Central Public Works Department.